AKG-PK/1Y/4.00

श्री राजीव शुक्ल (क्रमागत) : सर, आज की तारीख में इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 64 रुपए प्रति लीटर है। इससे महँगाई रुक ही नहीं सकती, क्योंकि इसका सीधा असर महँगाई पर पड़ता है। इसके लिए सरकार ने इतने दिनों में कुछ न कुछ किया, लेकिन अब consumer को कितना फायदा pass on होता है, वित्त मंत्री जी को यह बताने की कृपा जरूर करनी चाहिए।

सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि exports क्यों down हो रहे हैं? अभी दावोस में भी प्राइम मिनिस्टर ने promise किया, लेकिन इसके बाद भी हमारा export 30 मिलियन से 23 मिलियन तक आ गया। यह क्यों down हो रहा है? इसकी वजह से बहुत समस्या आएगी। इसलिए इस तरफ भी सरकार को देखना चाहिए।

सर, एक बात, जो हमने बीच में वित्त मंत्री जी से पूछी थी कि फिक्की के सम्मेलन में Morgan Stanley ने कहा था कि 6 हजार entrepreneurs बाहर चले गए, यहाँ से परेशान होकर, क्योंकि उनको इतना तंग किया जा रहा है, विभाग के अधिकारीगण उनके पीछे इतना पड़े हैं, इतने notices दिए जा रहे हैं कि इसकी वजह से वे चले गए। अगर entrepreneurs बाहर चले जाएँगे, तो नौकरियाँ कौन देगा? रोजगार तो सीधे-सीधे उनसे जुड़ा है, गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती। इसलिए private entrepreneurs में जो डर या भय है और वे बाहर जा रहे हैं, तो रोजगार कौन देगा, इसके लिए भी कदम उठाने चाहिए।

यह सही है कि Corporate Sector के 250 करोड़ तक के turnover पर 25 परसेंट टैक्स कर दिया है, जो अच्छी चीज है, लेकिन अब जो cess लगाया गया है, उसका कितना impact आएगा, अगर इस मामले में भी वित्त मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर सकें, तो बहुत अच्छा है। ...(समय की घंटी)...

सर, GST को लेकर एक समस्या यह आ रही है कि लोगों को कर्ज लेकर GST अदा करना पड़ रहा है। अगर आप इसका कुछ निदान निकालें कि किस तरह से जो व्यापारी और दुकानदार हैं, अगर उनको समय सीमा की कुछ ऐसी सुविधा हो, ताकि उनको वह दिक्कत न हो, तभी मुझे लगता है कि सुधार हो सकता है और GST को लोग स्वीकार कर लेंगे, वरना अगर बैंक से कर्ज लेकर GST देना पड़ा, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी।

सर, आज एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, हम तो इसकी तारीफ करेंगे। यह Money Bill के जरिए हुई, लेकिन चूँकि वह वित्त से सम्बन्धित है, इसलिए मैं इसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि judiciary की बात सुन कर और उनकी माँगों को मान कर जजों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। हाई कोर्ट तक के जजों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। चलो, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं कि यह अच्छी चीज है। अब उनकी तनख्वाह तो 2.5 लाख कर दी गई है, लेकिन आप judicial reforms तो लाइए। हर चीज में reforms हो रहे हैं, क्रिकेट में हो रहे हैं, हॉकी में हो रहे हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सबमें reforms हो रहे हैं, लेकिन judiciary में कोई reform ही नहीं हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : राजीव शुक्ल जी, आप समाप्त कीजिए। अब अगला नाम आएगा।

श्री राजीव शुक्ल : देखिए, 3 मिनट वाले को आपने 13 मिनट दिए, तो आपको मेरे साथ क्या problem है?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अभी आपके 7 और लोगों को बोलना है।

श्री राजीव शुक्ल : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी और बोलूँगा।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप judiciary के लिए कोई reform ही नहीं रखते हैं, आप कोई बात ही नहीं करते हैं, सरकार भी नहीं करती है। एक NJAC बना, उसके बाद उसमें कोई प्रगति नहीं है। अगर इसके बारे में भी मंत्री जी स्पष्टीकरण दें, तो बहुत अच्छा होगा।

अब मैं एक मिनट समय रेलवे पर लूँगा, क्योंकि इसमें रेलवे का बजट मिला दिया गया है और इससे रेलवे पर चर्चा होनी बंद हो गई है। अब कोई रेलवे की बात ही नहीं करता, बजट में इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। रेलवे का जो बजट है, मुझे लगता है कि लोग उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि पहले दिन उसका सूचकांक 5 परसेंट गिर गया। इसकी operational cost 95 प्रतिशत बताई गई है। इसका मतलब है कि रेलवे में सुधार करने के लिए, infrastructure बनाने के लिए और बाकी काम करने के लिए सिर्फ 5 परसेंट का cushion है। यह कैसे हो पाएगा, क्योंकि हाल यह है कि सारी रेलों का refurbishment करना है और नई रेल लाइनें बिछानी हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? Quality services provide करने के लिए पैसा नहीं है। अभी Civil Aviation

का data आया है कि यह almost बराबर हो रहा है, air passengers और railway passengers में थोड़ा ही अंतर रह गया है। लोग अब जहाज से चलना ज्यादा prefer कर रहे हैं, क्योंकि उनको रेलवे में सुविधा नहीं मिल पा रही है, पैसा ज्यादा देना पड़ता है, टाइम की बर्बादी भी बहुत हो रही है और समय से trains भी नहीं चल पाती हैं। इसलिए यह जो अंतर पहले बहुत होता था, अब कम होता जा रहा है। अभी 400 जहाज और order हुए हैं। अगर वे आ गए, तो रेलवे बहुत बुरी स्थिति में फँस जाएगी, क्योंकि लोग जहाज से जाना ज्यादा prefer करेंगे। मान्यवर, खाना ट्रेन के अन्दर भी खराब है और प्लेटफॉर्म का भी खराब है। पीयूष गोयल जी काफी मेहनती मंत्री हैं और सुधार में लगे रहते हैं, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, policy की चीजें हैं। इनके लिए प्रावधान चाहिए, पैसा चाहिए। वे कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है। अगर पैसे की कमी नहीं है, तो सुविधाएँ ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं? Freight भी गिर गया है। रेलवे की journey तो इतनी अच्छी होती है कि विदेश में इससे कितना फायदा हो रहा है। शहर का जो सेंटर होता है, वहाँ रेलवे स्टेशन होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, आराम से जाएँ, उनको कोई दिक्कत न आए। ...(समय की घंटी)... लेकिन इसके बाद भी रेलवे का profit क्यों गिरता जा रहा है और passengers कम क्यों होते चले जा रहे हैं? रेलवे सुरक्षा के लिए काकोदकर कमिटी की जो recommendations थीं, उनके लिए जो बजट का प्रावधान करना चाहिए था, वह प्रावधान अभी तक इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको इसके लिए प्रावधान करना चाहिए।

सर, अभी मेरे पास बहुत points हैं, लेकिन आप कहते हैं कि दबाव और pressure है, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ और इसलिए मुझे अपनी बात समाप्त करनी पड़ रही है।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : श्री संजय सेठ। आपके पास 2-3 मिनट का समय है।

(1जेड/एससीएच पर आगे)

SCH-PB/4.05/1Z

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, यह जो बजट है, यह बहुत ही निराशाजनक दिख रहा है, क्योंकि आम जनता को इस बजट से बहुत उम्मीदें थीं। इस बजट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, वह है दस करोड़ लोगों के लिए पांच लाख रुपये का बीमा, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसको दो भागों में बांट दिया। इसमें पहला था स्वास्थ्य केन्द्रों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अपने नज़दीक ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और दूसरा था...(व्यवधान)...

नेता विरोधी दल (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : वाइस चेयरमैन साहब, कल तक बजट पर चर्चा के लिए छः घंटे बचे थे, लेकिन पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने unilaterally उसको घटा कर तीन घंटे कर दिया। मैंने सुबह भी कहा था कि अगर पार्टीज़ का समय काटना है, तो दूसरी पार्टीज़ का समय मत काटो। इसकी वजह से

सारा टाइम-टेबल गड़बड़ हो गया है। जहां हमने एक-एक मेम्बर को बोलने के लिए 10-10 या 15-15 मिनट रखे थे, अब वे तीन मिनट में कन्वर्ट हो गए हैं।

قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد) : وائس چیئرمین صاحب، کل تک بجٹ پر چرچا کے لئے چھہ گھنٹے بچے تھے، لیکن اب پارلیمنٹری افیئرس منسٹر صاحب نے اس کو unilaterally چھہ گھنٹے کر دیا۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ اگر پارٹیوں کا وقت کاٹنا ہے، تو دوسری پارٹریوں کا وقت مت کاٹئے۔ اس کی وجہ سے سارا ٹائم ٹیبل گڑبڑ ہو گیا ہے۔ جہاں ہم نے ایک ایک ممبر کو بولنے کے لئے دس-دس یا پندرہ-پندرہ منٹ رکھے تھے، اب وہ تین منٹ میں کنورٹ ہو گئے ہیں۔

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अब जैसा है, ठीक है।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जब सदन बड़े आराम से और शांति से चल रहा था, ऐसे में अगर सदन दो घंटे और चल जाता, तो क्या फिक्र थी? आज के लिए हमारे पास छः घंटे बचे थे, उस पर आपने एकदम slab लगा दिया और पूरे तीन घंटे कम कर दिए। कल सदन तकरीबन 6-7 घंटे चला था, इसलिए आज छः घंटे और बाकी थे। इसकी वजह से पूरा गड़बड़ हो गया है।

جناب غلام نبی آزاد : جب سدن بڑے آرام سے اور شانتی سے چل رہا تھا، ایسے میں اگر دو گھنٹے اور چلا جاتا، تو کیا فکر تھی؟ آج کے لئے ہمارے چھہ گھنٹے بچے تھے، لیکن اس پر آپ نے ایکدم slab لگا دیا اور پورے تین گھنٹے کم کر دئے۔ کل سدن تقریبا چھہ-سات گھنٹے چلا تھا، اس لئے آج چھہ گھنٹے اور باقی تھے۔ اب اس کی وجہ سے پورا گڑبڑ ہو گیا ہے۔

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : अब जो हो गया, ठीक है। संजय जी, आप आगे बोलिए।

श्री संजय सेठ : माननीय मंत्री जी ने इस बजट को दो भागों में बांटा है, जिसमें एक भाग स्वास्थ्य के लिए है। इसमें पहला है, स्वास्थ्य केन्द्रों को बढ़ावा देना, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नज़दीकी केन्द्रों में उपलब्ध हों। दूसरा है, 10 करोड़ गरीब लोगों को पांच लाख रुपये के बीमे की सुविधा देना। मैं दूसरे बिंदु के ऊपर बोलना चाहता हूं, जो बहुत ही प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। महोदय, अगर इसके आंकड़े देखे जाएं, तो इस साल स्वास्थ्य के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है, वह 52,800 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले साल इसके लिए 51,580 करोड़ रुपये का बजट था, यानी इस बजट में केवल 1,250 करोड़ रुपये ही बढ़ाए गए हैं।

दूसरी तरफ एजुकेशन सेस के नाम पर जो तीन प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर अब 4 प्रतिशत कर दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है, 'हेल्थ एंड एजुकेशन सेस '। इसका मतलब तो यह है कि आप जनता से एक प्रतिशत लेंगे और फिर उसी चीज़ को गरीबों में बांटेंगे। इस सरकार ने अपनी तरफ से इसमें कोई कॉंट्रिब्यूशन नहीं दिया है, जनता से वसूल करके जनता को ही वापस करने की बात है और वह भी किसी हालत में पूरा नहीं हो सकता है।

तीसरा, इसमें डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए कहा गया है, जिसके लिए 1,200 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं, यानी एक सेंटर बनाने के लिए केवल 80,000 रुपये एलोकेट हुए हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी जो सेंटर्स चल रहे हैं, उन सारे के सारे सेंटर्स में न तो उचित रख-रखाव है, न उनमें कर्मचारी हैं और न ही मेडिकल का सामान है। उन सारे सेंटर्स को छोड़कर अब ये नये सेंटर्स बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसमें मेरा यह कहना है कि जो सेंटर्स पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को आप ठीक कराएं और उन्हीं पर पैसा लगाएं। नई चीज़ करके क्या फायदा होगा?...(व्यवधान)...

महोदय, अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में दुर्घटना हुई और वहां एक साथ सैकड़ों बच्चे मर गए। वहां पर ऑक्सीज़न की कमी है, साथ ही पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। देश की जनता के स्वास्थ्य के लिए इस तरह की चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाए इसके कि आप लुभावनी चीज़ें दिखाएं और उनको पूरा भी न कर सकें। दो साल पहले के बजट में भी इसी तरह का एक प्रोविज़न था, जिसमें उन्होंने एक लाख रुपये का बीमा करने की बात कही थी, लेकिन आज तक 30,000 रुपये के बीमे से ऊपर नहीं दिया जा रहा है।

तीसरा, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में यहां तक कहा कि एक करोड़ मकानों में से 93 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि इनके पास ये आंकड़े आ कहां से रहे हैं?

इस संबंध में लोक सभा में जब एक सवाल किया गया था, तो उसके जवाब में इन्होंने बताया कि अभी तक केवल 21 लाख मकान बने हैं।

(2a-rpm पर जारी)

RPM-SKC/2A/4.10

श्री संजय सेठ (क्रमागत): महोदय, इस तरीके से बताया जा रहा है कि 93 लाख मकान बन चुके हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अभी तक केवल 21 लाख मकान ही बने हैं। ये सारी चीजें असत्य हैं। इसमें कुछ नहीं है और जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है।

महोदय, दूसरी बात इन्होंने अपने बजट भाषण में रीयल एस्टेट के पाइंट में यह बताई कि जमीन के दाम सर्कल रेट के हिसाब से होंगे। उसमें अगर इन्कम टैक्स में 5 परसेंट का डिफरेंस होगा, तो वह मान लिया जाएगा। अगर दिल्ली को देखें, तो यहां जमीनों के दाम बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन सर्कल रेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी भी शहर का सर्वेक्षण कराएं, तो यही हाल मिलेगा। अब गरीब आमदी या कोई भी आदमी मकान खरीदे, तो उसके लिए स्टाम्प-ड्यूटी ज्यादा दे, उसके बाद इन्कम टैक्स भी ज्यादा दे, तो यह ठीक नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री संजय सेठ: इसलिए इसमें कोई प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए था कि उसका एक सर्वे करा के उसे 5 से 10 परसेंट कर दिया जाए, धन्यवाद। (समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Thank you. Now, Shri N. Gokulakrishnan; you have only two minutes to speak.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बजट पर चर्चा चल रही है और न वित्त मंत्री हैं, न राज्य मंत्री (वित्त) उपस्थित हैं। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यहां राज्य मंत्री (वित्त) उपस्थित हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है। वित्त राज्य मंत्री उपस्थित हैं। ...(व्यवधान)... अच्छा, आपस में बात मत कीजिए। बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Naqviji, please, no cross-talk. ...(Interruptions)... Jairamji, no cross-talk, please. You are one of the best parliamentarians.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (PUDUCHERRY): Hon. Vice-Chairman, Sir, due to paucity of time, I would cut down all my points on the General Budget and come straightaway to the issues concerning Puducherry.

Sir, talking about grant of Central assistance to States and Union Territories, a share of the total tax collected at the Centre is given to the State Governments based on the Finance Commission's recommendations. In the case of Union Territories without Legislatures, the entire budget requirement is met by the Government of India after taking all receipts from the Union Territories. In the case of Union Territories with a Legislature, like

Puducherry, normally the entire gap between their budgetary requirement and their resources is met by the Government of India.

Sir, the Union Territory of Puducherry has implemented the Seventh Central Pay Commission recommendations and has requested the Government of India for additional funds to the tune of Rs. 750 crores. But, so far, the Government of India has not given even a single rupee to Puducherry for implementing the recommendations of the Seventh Central Pay Commission. The Central assistance allocated to the Union Territory of Puducherry for the current financial year is Rs. 1,476 crores; for the previous year it was Rs. 1,411 crores. But, in recent years, this has been stopped and instead, Central assistance with a four per cent increase over that of the previous year has been fixed.

Sir, the Union Territory's resources have been affected considerably by various factors like GST, ban on bar licence on highways and ban in the real estate sector. On the one hand, expenditure has increased due to the implementation of the Seventh Pay Commission recommendations and, on the other, the income has come down. Thus, the Union Territory of Puducherry is not able to carry out development programmes since the

entire receipts are being used for committed expenditure like salaries, pension, payment of interest and repayment of loan. I appeal to the hon. Finance Minister to increase the share of Central assistance to the Union Territory of Puducherry at least by 20 per cent every year.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Please conclude now.

SHRI N. GOKULAKRISHNAN: Sir, I would take just one more minute.

Sir, I wish to invite the kind attention of the hon. Union Railway Minister to a long-pending demand of the Union Territory of Puducherry for a railway link from Tindivanam to Cuddalore via Puducherry. A lot of commuters visit places of pilgrimage like Karaikkal, Nagoor and Velankanni from Chennai. Connecting Tindivanam and Cuddalore through a railway link would lessen their travel time.

(CONTD. BY HK/2B)

HK-PSV/2B/4.15

SHRI N. GOKULAKRISHNAN (CONTD.): Sir, I appeal to the hon. Union Railway Minister to look into this long-pending demand for immediate consideration. Similarly, I appeal to link Peralam with Karaikal, which is also

a long-pending demand. In fact, I raised this matter and discussed in detail about the viability when I attended the Railway Committee meeting organized by the General Manager of South Zone of Railways at Madurai last month. With this, I conclude my speech and I welcome the welfare schemes announced by the hon. Finance Minister and I also appeal to him to consider my demands favourably. Thank you.

(Ends)

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, धन्यवाद। श्री नरेश गुजराल जी, आपके तीन मिनट हैं।

SHRI NARESH GUJRAL: No, Sir. I am the leader of my group. We have 18 Members. I must have 10 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Your Party has ten minutes in total and there are three Members to speak. ...(Interruptions)...

SHRI NARESH GUJRAL: I am sorry, Sir, I won't speak; somebody else to speak. ...(Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल: सर, यह बहुत गलत है। ...(व्यवधान)... *

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप बैठिए। ...(व्यवधान)... नरेश गुजराल जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... शुक्ल जी, आप अपनी जगह पर जाइए।...(व्यवधान)...

Shukla*ji,* please go to your seat. ...(Interruptions)...

श्री नरेश अग्रवालः * ...(व्यवधान)... * ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्लः * ...(व्यवधान)... *

---

*Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): आप सब लोग बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... You sit down. ...(Interruptions)... I will take care. ...(Interruptions)... आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... नरेश गुजराल जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)... बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... टाइम वेस्ट जायेगा, बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... गुजराल जी, बोलिए। ...(व्यवधान)...

SHRI NARESH GUJRAL (PUNJAB): Sir, first of all, I would like to start by expressing my sympathies with my follow Members who are here. Commitments were made to Andhra Pradesh in this House which, unfortunately, collectively have not been kept and I feel sorry that their demands are not being met and I hope that the hon. Finance Minister will look at their demands favourably.

Sir, having said that, I feel that this is the most challenging Budget for the hon. Finance Minister since this Government came to power. Why is it challenging? It is because oil prices have hardened and are today in the vicinity of 65 to 70 dollars a barrel. For four years, you had the cushion of soft oil prices with which you could pursue giving money to the social sector. Secondly, Sir, there is an acute farm distress in the country. Thirdly, there is an under-utilised capacity in manufacturing and the power sectors which are not creating fresh jobs. At the same time, he has to maintain fiscal discipline because the country wants to send the message to international investors that we are fiscally responsible so that FDI keeps coming to India. Having said that, I congratulate the Finance Minister that he has taken a holistic view by pumping in money to the rural sector, and I call it a paradigm shift in the way we look at agriculture and agriculturists in this country. Sir, it was very strange that despite the fact that 65 per cent of India's population was dependent on the farm, 49 per cent of the jobs were created in the agriculture sector. Yet, we were short-changing our farmer by not giving him adequate prices for his produce. What were we doing? We were saying, let's not give him a high price because that will create inflation. So, the poor farmer was suffering. Every time international prices went up, we

would put a ban on export because again we wanted to protect a constituency in India which was the urban constituency and the farm sector kept suffering. So, I congratulate the Finance Minister that he has said and kept the promise that the farmer will get 150 per cent of his cost which means cost plus fifty per cent. Now, Mr. Chidambaram, Mr. Neeraj Shekhar and many others have raised a question about formula. Is it A2 plus FL or C2? Sir, I am not getting into any formulas. Yesterday, one of the Congress Members, Mr. Chidambaram probably, said that in their tenure they doubled the prices of the farm sector in ten years. Neeraj*ji*, that works out to six per cent compounded per annum. This is what the farmer was getting when the inflation rate was in double digits.

(Contd. by DPS/2C)

DPS-DS/2C/4.20

SHRI NARESH GUJRAL (CONTD.): So, every year, the poor farmer was forced to commit suicide. Thank God, now the Finance Minister has said that the farmer will get just deal. So, by not getting into the details of which formula it is, I will only urge the Finance Minister that the next crop is coming in two months. We have raised the hopes of the farmer of this country. They are expecting a new deal, a big deal. Please, do not let down the

farmer of India because if you do, you will see the kind of despair, suicides and frustration that this country has never seen before. So, as I said, I am not getting into the formula, but I do hope that the farmer will finally get a proper deal. Sir, secondly, how does a farmer get so poor and eventually commit suicide when he is so frustrated? Number one, he does not get adequate price for his produce. Number two, the healthcare cost. Somebody falls ill in his family, he begs, borrows at high interest rate and then gets the patient treated. And, third is marriage expenses. This Budget has taken care of the first two. Adequate farm prices and making sure that the poor in this country will be treated by the Government up to 5 lakhs per family which I think is a phenomenal announcement. But, again, he must be honoured in letter and spirit. Only then will the poor of this country feel satisfied. And, I would also urge the Prime Minister the way he has carried the campaign of 'Swachh Bharat', I hope something is done that we curtail expenses on marriages in this country and some kind of a social campaign needs to be unleashed because that will help the farmer.

Sir, having said that, jobs have to be created. Now, the Finance Minister has said, we will pump money into the farm sector. Six lakh crore is going into the infrastructure sector, he is making sure that the textile sector,

which is the second largest generator of jobs after the farming sector, will get its due and jobs will be created there. And also he has tweaked the labour laws; till now, it was that you could hire but not fire, but by giving fixed term contracts, this will ensure that industry starts to hire more people. Sir, I am an optimist. The way the BJP, the NDA has followed economic policies, I am convinced that we will see double digit growth very soon and the proof of that is the way FDI is coming into India. They are not fools. They know that this country will have the market, this country is growing and this country is following the right economic policies and that is why they are coming to India. And, this is very important, Sir, because our domestic rate of savings is now stagnant at 29 per cent for a very long time. We need the FDI investment. This year it is about 60 billion dollars and I think it will increase as our market becomes better. Because what happens is when there is a demand, only then factory starts working into full capacity. And this is what this Finance Minister is doing. He is creating the demand. And this will set in motion a virtuous cycle. When factories start working to full capacity, they will have to hire more people; when more people are hired, that will create more demand and when there is more demand, only then private sector investment will start coming in and I have no doubt in my mind

that the NDA will ensure that this economy gets regenerated. This Budget has given it a kick-start and I am convinced that going forward, this country will soon see double-digit growth and I congratulate the Finance Minister for that. Thank you very much, Sir. (Ends)

DR. K. KESHAVA RAO (ANDHRA PRADESH): Sir, before I start, I am distraught for the simple reason, we seem to have thrown to the winds the very rules of this House. And now the Chairman comes and says that if anybody is standing in the Well, it means disorder of the House and it cannot be put into order. Yet, we allowed. Then we seem to have forgotten the political idiom when we talk. That is also something which has really hurt most of us, being in this House or outside the other Legislatures.

(Contd. by KSK/3D)

KSK/DS/4.25/2D

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD.): But, the question today is about the Budget. I am very much interested in talking about the Budget, but what has really provoked me most is my friends from Andhra, for whom we have all expressed sympathies. In fact, I was the first man, when a Private Member Bill was taken up here, who spoke here and went in their support, if not rescue. It is Mr. Jairam, who wrote this book. I am really taking up an

objection today that one man, who could neither become friends with us nor with them, wrote the rules and also the law. He was the most harassed man in those fifteen days, and I said this here in this House also.

Today, the Prime Minister goes on record to say on the floor of the House that bifurcation was done unscientifically. I don't understand it because I know very little English. I have not still understood as to what exactly he means by unscientific bifurcation of a State. I can understand my friend, who was with me, who is now the Chief Minister of Andhra today. He was with me as a junior Minister when I was a Cabinet Minister. He seems to know more about language, as Mr. Chidambaram was saying that we have added new words to the English language, like *jumlas*, etc. Now, tell me, what exactly did we want? We are all for it. That is one. Now, what are they trying to say about Telangana? I think, my sister, Renukaji, will excuse me when I say this. I am with them, as far as their demand is concerned, if they want the implementation of the Andhra Pradesh Re-organization Act, although I had total objection to it. Earlier also, I had said this to Mr. Jairam Ramesh, who is very much here, who is the author of the Act. But, today, while agreeing with them, when they say that something wrong had been done in the Act, I would like to say that they should

understand that the Parliament has not done anything wrong. They are casting aspersions on the Parliament which has passed this Act. Have they ever thought about this aspect? Only because we are keeping quiet, only because all Members are coming and supporting them, do they think what they are doing is good for the Parliament? This Parliament has passed this Act, not one House, but both the Houses - the Lok Sabha and the Rajya Sabha. After that, we had discussions for fifteen days about framing the rules. The very Member, who is sitting here, had called them for the rules. They got all that they wanted. Today, most of the Members are here. I don't want to repeat this. We have been expatriated for sixty years. We did not bother because all that we wanted was a State. Now, it is a reality. Today, if there are any votes at all, in my Telangana, it is not me who does it; it is you who are giving the contracts there; it is you who are purchasing all the land there; it is you who were purchasing, only the day before yesterday, all the flats there. I have never complained about it. But, today, you come and compare. We did not have water. Mr. Vice-Chairman, Sir, you are aware. When you went out from Telangana, we did not have any fight at all. The Prime Minister came and said yesterday in Lok Sabha that when they had carved out three States, there was no problem. Sir, we were divided.

My own State was divided into three parts. There was no hue and cry. A part went to Maharashtra. A part went to Karnataka. Nothing happened because we all are hard-working people. One was not expanded; one was not the sufferer. Forget about that. I am trying to close that chapter. But, the question today is: there are only two rivers. They flow only from Telangana. Two-third of these rivers flows in Telangana. Total capital investment is in Telangana. Eighty-three per cent capital investment is in Telangana. But only eighteen per cent is used here. When the Congress people had constituted a Committee, we fought and got whatever we could, but we thought that we would discuss it later right here on the floor of Rajya Sabha. The present Chairman of Rajya Sabha, Shri Venkaiah Naidu, who was then an opposition Member, asked for a few concessions. He asked for seven concessions. The Prime Minister of the day agreed to that. First, he said that he would look into that, and then he said that he agreed to that, and a Cabinet Note was also prepared. Nobody objected to it. But what is that we are asking now? Please, think again. I am not opposing you. You should get more. What is wrong if the Centre gives you more money? What is wrong if the Centre gives you ten industries more?

(Contd. by 2E – GSP)

GSP-MCM/4.30/2E

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD.): You get more but don't grouse over others. Do not have grievance against others if something is not given to you. We are still subject to exploitation, which I was subjected to twenty years back. This thing should be kept in mind by all the people. I know, you have been rich; I know, there is nothing wrong in that, and, if there is a chance, we will try to come out, the way we are coming.

Yesterday, the Minister said -- I am asking all my other Members to know -- we all know that none of you were also objecting to it -- but let it not be as if they have been denied and the other man is getting it. Sir, according to the statement given by the Finance Minister yesterday, the break-up of the moneys released is Rs. 4,400 crore in 2014-15; Rs. 2,000 crore in 2015-16; Rs. 4,500 crore in 2016-17; Rs. 2,500 crores in 2017-18, and the total is something like Rs. 13,000 crore. All right. This must be worked out because not a single paisa except Rs. 2,000 crore came to Telangana. All that Mr. Jairam Ramesh said in those days was 'equality'. Whatever it is, if we are getting AIIMS, you are getting it. If we are getting IIM, you are getting IIM. If we are getting the university, you will get the tribal university. Did not you see that? You set up thirteen institutions. Did you give me one?

You gave them three. We kept quiet. We thought we will have to fight. We don't go with the begging bowls to those people as long as people are with us. What is the question today? That is why, when the Prime Minister came or even the Chairman came and said about 2,000 crore of rupees, I said, "hell with this; who are you to give." It is my money. I give Rs. 30,000 crore every year to the Central pool. Nobody is giving me something out of charity. This should be understood. Yesterday, when the Prime Minister came and said, हमने तो तीन स्टेट किया, कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने तो तीन स्टेट करवा लिए, कोई गड़बड़ी नहीं हुई।.....(व्यवधान).....

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है, केशव राव जी।

डा0 के0 केशव राव : नहीं साहब, जरा सुनिए। मैं कभी इस चीज को लाता ही नहीं था, मैं उनका साथी हूं। कल रात रमेश साहब मेरे पास आए थे और मुझसे बोले थे कि साहब, हम यह रेज़ कर रहे हैं। मैंने कहा रेज़ करिए। But do not try to act like that बिकॉज़ किस तरीके से हम रूल करते हैं, आपको मालूम है। हमारी पॉपुलेरिटी पर एक अंगुली भी मत दिखाइए। आपने 5 मर्तबा कंटेस्ट किया, डिपॉज़िट लूज़ कर दिया, वह भी याद रखेंगे। कल कंटेस्ट करेंगे तो डिपोजिट लूज़ कर देंगे, वह भी याद रखेंगे। जो भी हो, चाहे आप हों या आपके दोस्त हों, जब डिपॉज़िट आएगा तो हम छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे, क्लोज कर लेंगे, अगर डिपॉज़िट आ गया। तो ठीक है, वह बात नहीं बोल रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : धन्यवाद।

डा0 के0 केशव राव : मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। नीरज जी, मैं तो ओपन कर रहा हूं, हर वक्त तो वही बोलता हूं न। उनके प्रेजिडेंट आएं तो भी हम लोग बोलेंगे। ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ज़रा कंटेस्ट करने के लिए बताइए, वह बतला देते हैं। वह नहीं है, मैं क्यों बोल रहा हूं। We are with you but this is something else. How can you be allowed to stand there? One of my friends asked for a chair for you to sit. All that we wish is to ask the Finance Minister, ask the Government to sort out these issues. If all of us feel that something wrong has been done to Andhra, if we feel that something has gone wrong, let the Government sit and sort it out. You have not done that during 12 days when the Reorganisation Act was passed. Within 12 days, they completed the rules. We thought that if something is still left, we will sort it out.

So, here is a question of money. They say that they have already given you 12,000 or 13,000 crores of rupees. If it still needs to be given, let them give it but let them not do this. यह मैच फिक्सिंग को आप लोग बस करो। नहीं तो एक आदमी को आप रूम से निकाल देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, एक आदमी को कुर्सी देते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यह? मज़ाक हो रहा है इस पार्लियामेंट का? अब तेलंगाना के बारे में बताइए। हम लोगों ने क्या नहीं किया? हमने आपसे नहीं पूछा है। आपने आज तक इस बजट में एक भी चीज के बारे में नहीं कहा। महोदय, आप

जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। चूंकि आप तेलंगाना जानते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने एक चीज दी। हम इंडिया की one of the biggest irrigation projects, Kaleshwaram, build कर रहे हैं। ...(व्यवधान)..... बाद में पूछा कि कुछ पैसे दे देते क्या। जरूर यह तो नेशनल प्रोजेक्ट है, एक मॉडल है, शायद मेरा इतना अच्छा हिन्दी नहीं है, उनकी हिन्दी अच्छी होगी।

(2F/SC पर जारी)

SK-SC/4.35/2F

डा0 के.केशव राव (क्रमागत) : शायद उनकी हिन्दी मेरे जैसी नहीं होगी, उनकी हिन्दी अच्छी होगी, जिसे मैं नहीं समझ सकता हूं, वह अलग बात है। उन्होंने कह दिया कि यह मॉडल बन जाएगा। हमने बाद में उनसे कहा कि आप दस हज़ार करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन आज तक हमें एक पैसा नहीं दिया गया। हमारे पास पहले पानी नहीं था, आप इस संबंध में जानते हैं क्योंकि आपके पास पानी नहीं पहुंच सकता, पानी के बिना तो कोई स्टेट नहीं चल सकती तो हमने क्या किया - हमने पहली मर्तबा lift irrigation से..(समय की घंटी).. महोदय, एक मिनट। Lift irrigation से one crore acres of land we have covered. We have already covered three projects. She has one. Within three months we have completed the project in Bhadrachalam. Like that, we are trying to do it. आपने अपने दिल में रख लिया है कि ये तो अपने नहीं हैं, चलिए, हम लड़ लेंगे। हम लोग लड़ेंगे भी - आप उसकी फिक्र मत कीजिए।

अब मैं आपके बजट की बात करता हूं। आपके बजट में ट्रेन के लिए हम लोग इतने साल से पूछ रहे हैं। चालीस साल से हम लोग काज़ीपेट में कोच फैक्टरी की मांग कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में तीन मर्तबा फाइनेंस मिनिस्टर साहब बोले, no, no, this time we are going to give you AIIMS. उन्होंने announce किया, on the floor of the House. But no AIIMS. वह हवा में आ रहा होगा या शायद लॉरी में आ रहा होगा, लेकिन वह एम्स बहुत जल्दी आएगा। महोदय, उन्होंने हमें दो लाइन्स दीं, एक-एक बोल देता हूं।..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : केशव राव जी, अब समाप्त कीजिए।

डा0 के.केशव राव : महोदय, मैं लास्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ बोलना चाहता हूं। आप एक्ट छोड़ दीजिए, बातें छोड़ दीजिए, promises छोड़ दीजिए, वहां पर जो तारीफें करते हैं, हर सेंट्रल मिनिस्टर आकर कहता है कि इतना बड़ा हमने सोचा ही नहीं। आप उसे भी छोड़ दीजिए। Constitution में लिखा हुआ है कि every State shall have one High Court. वहां पर आज तक हाई कोर्ट नहीं आया है। At some place, you start giving it. But in our case, no sympathy has ever come from you. आप इस बारे में सोचना शुरू कीजिए, वहां हाई कोर्ट दीजिए। वहां पर कौन suffer कर रहा है - हम लोग suffer कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो कुछ भी हो..(समय की घंटी)..

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल) : ठीक है, केशव राव जी, धन्यवाद। श्री शमशेर सिंह मन्हास।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it is there in the Act and the Government has delayed ..(Interruptions).. This is completely inexcusable. ..(Interruptions)..

डा0 के.केशव राव : महोदय, मैं एक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं तो Constitution की बात कर रहा हूं। Constitutional provision होने पर भी आप नहीं करते तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी?

उपसभाध्यक्ष (श्री बसावाराज पाटिल): ठीक है, केशव राव जी, धन्यवाद।

डा0 के.केशव राव : महोदय, मैं इतना कहते हुए, अगर आपने मुझे चांस दिया तो मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूं, मुझे यह issue join करना था, वरना as far as the Budget is concerned, सब लोगों ने डिटेल में बातें कह दी हैं, उस संबंध में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। आप कुछ बोल रहे हैं। ये economic stability की बात कर रहे हैं। उन्होंने 12 सवाल पूछ लिए हैं, हमारे देरेक साहब ने दस सवाल पूछ लिए हैं, मैं उन questions को छोड़कर दूसरे questions आपसे पूछना चाहता हूं। आप macro stability, fiscal consolidation और slippages की बात कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? On the other side, I don't know whether there is any economist, but I can ask Mr. Jairam Ramesh or Gujral*ji*. Tell me what this slippage means. It means nothing but increase in the deficit, simple economics. Or it means increase in inflation, simple economics. Is it not true? Now, the second question is, गुजराल जी ने कहा कि यह बहुत difficult challenge है, सख्त challenge है। It is true because post demonetization, you had your problems. But what did you do

to ..(Interruptions).. In the demonetization, ..(Interruptions).. आपको टाइम अभी दिखाई देता है साहब। ..(व्यवधान)..आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अब आपको सिर्फ टाइम ही दिखाई दे रहा है। अब आपको टाइम बराबर दिखेगा। महोदय, मैं आपके थ्रू मंत्री जी से पूछता हूं कि you got funds after demonetization. It must go to Jan Dhan account holders or whatever it is. We thought it would go because the economic prudence suggests that. (Time-bell) But what did we do? ..(Interruptions)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BASAWARAJ PATIL): Keshava Rao*ji*, please conclude it within one minute.

DR. K. KESHAVA RAO: Anyhow, I would not say everything is wrong in this Budget because I am not going to join issue with them, nor am I trying to make a point there. इसमें one-upmanship नहीं है। There are fundamental difficulties which are overlooking those things. There were twelve questions from there and ten questions from here. A few of them you might answer well, a few of them you will ..(Interruptions).. वह आप देखिए, वरना the big opportunity that you got is missed. I would say in the Budget, you had a good opportunity, which you have missed.

(Ends)

(Followed by PRB/2G)

PRB-YSR/2G/4.40

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, कल से मैं इस बजट पर चर्चा सुन रहा था। बजट पर चर्चा सुनते-सुनते कुछ महानुभावों ने इसको questionnaire बना दिया। किसी ने 12 प्रश्न पूछे, किसी ने 14 प्रश्न पूछे, किसी ने 8 प्रश्न पूछे। इसका मतबल यह है कि हम इतने सक्षम हैं कि हमसे आप कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि हम कुछ अच्छा करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं और आजादी के उपरान्त 55 वर्ष तक कांग्रेस ने, जिसमें से 40 वर्ष एक ही वंश ने राज किया है और 15 वर्ष उनके जो बाकी साथी थे, उन्होंने किया है। ये कुल मिलाकर 15-16 हजार दिन बनते हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, वह प्रदेश जम्मू-कश्मीर बड़ा संवेदनशील है। हमारे LOP साहब, यहां पर होते, हमारे आज़ाद साहब यहां पर होते, तो मैं उनसे पूछता कि वे कौन सी जगह से आते हैं, किस प्रकार का वह जंगल है और वहां कौन-कौन सी सुविधाएं प्राप्त हैं ? आज अगर देखा जाए तो वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर सड़क नहीं है, बाकी की बात तो आप छोड़ दीजिए। यहां तक कि वहां पर बच्चों के रहने के लिए जगह तक नहीं है। उनके पास एक ही कमरा है और वह भी पूरा लकड़ी का बना हुआ, जिसमें पूरा परिवार रहता है। वे मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, तो वे पिछले 60 सालों से मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित हैं ? 55 वर्ष राज करने के उपरान्त क्या कांग्रेस ने उस दिशा में विचार नहीं किया ? आज़ाद साहब वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं पूछना

चाहता हूं कि वहां पर आज तक जो कुछ होना चाहिए था वह क्यों नहीं हुआ? आज तक भी वहां सड़क नहीं है। मैंने वहां एक गांव adopt किया है, जिसे आदर्श गांव में रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 किलोमीटर steep चढ़ाई है, जो आप 10 घंटों में भी नहीं चढ़ सकते हो। आज भी सड़क के नाम पर पगडंडी है, जंगल से आते हुए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप dispensary को छोड़िए, स्कूल को छोड़िए, वैटरनेरी हॉस्पिटल को छोड़िए यहां तक कि वहां पर पंचायत घर तक नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर लोग रहते होंगे ? जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है, पक्की छतों के निर्माण की बात तो आप छोड़ दीजिए, उनके बारे में कौन सोचेगा और कौन विचार करेगा ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जब तक दूर-दराज कंदराओं में बैठे हुए व्यक्ति को, हर प्रकार की सुविधाएं न मिल जाएं, तब तक हमको कार्य करना पड़ेगा। हम उसी राह पर चल पड़े हैं और उसी राह को आज हम देख रहे हैं। इस प्रकार से जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हमारी सरकार उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। जिस प्रकार का 55 वर्ष तक आपका राज रहा और 15 वर्ष एक ही वंश का राज रहा है, पिछले 70 सालों में वहां पर क्या हुआ है ? मैं अपने प्रदेश की बात कह रहा हूं और मैं उससे बाहर नहीं जाना चाहता हूं, अगर मैं पूरे देश की बात करना चाहूंगा, तो पूरा देश इसी हालत से गुजर रहा है। चाहे आदिवासी क्षेत्र रहा हो, चाहे नार्थ-ईस्ट रीजन रहा हो, चाहे तमिलनाडु का क्षेत्र रहा हो, पूरे देश में सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वहां पर वे सुविधाएं कौन पहुंचाएगा ? वहां पर कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए ? जो

लोग वहां पर रहते हैं क्या उन्हें जीने का हक नहीं है ? क्या वे लोग नहीं चाहते हैं कि उनको भी सुविधाएं मिले ? वे भी BA कर सकें, MBA सकें, Medical College में पढ़ने जा सकें? वहां पर तो एक छोटा सा स्कूल तक नहीं है, तो वे क्या पढ़ पाएंगे ? इसलिए इन सब चीजों के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए, आज हमारे नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, उस राह पर चलने का प्रयास किया है और ईमानदारी से किया है जिससे कि यह देश आगे बढ़ सके।

(2H/GS पर जारी)

GS-VKK/2H/4.45

श्री शमशेर सिंह मन्हास (क्रमागत) : उन लोगों में यह कैसे विचार हो सकता है? उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हमारे 40 प्रतिशत लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, करीब 10 करोड़ परिवार आते हैं, 50 करोड़ की आबादी आती है, जिनके लिए कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के माध्यम से अगर देखा जाए, तो किसी को किडनी फेल्योर होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है और किसी को दूसरी बीमारी लगती है, इनके इलाज पर बड़े-बड़े खर्चे आते हैं। जो लोग कंदराओं में रहते हैं, उनके पास जीवन यापन के लिए साधन नहीं हैं, तो वे लोग कहां से चार लाख रुपये, पांच लाख रुपये इलाज करवाने के लिए देंगे, स्वास्थ्य को ठीक करवाने के लिए देंगे, वे कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक करवाने के लिए जाएंगे, वे कैसे आपरेशन करवाने के लिए जा पाएंगे? इसीलिए सरकार की ओर से उनके लिए पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा की योजना बनायी गयी है, जो कंदराओं में रहते हैं। हम तो केवल सोचते हैं, विचार करते हैं और विचारों को

क्रियान्वित भी करना पड़ेगा। इन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वे पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बंधुओ, जिस प्रकार से पहाड़ों पर किसानी होती है, आपने देखा होगा कि वहां पर ट्रेक्टर नहीं चलता है, वहां पर हल से जुताई नहीं हो सकती, वहां पर सिर्फ कुदाल से कुदाली करानी पड़ती है और धीरे-धीरे वहां पर किसान अपनी खेती-बाड़ी प्रारम्भ करते हैं- चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, वह कुदाल लेकर सुबह से शाम तक कुदाली करता है, फिर चार-चार, पांच-पांच महीने बाद एक फसल पैदा होती है। वहां पर सात महीने तो बर्फ रहती है, इसलिए वहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहां पर एक कमरे के अंदर लोग अपना जीवनयापन करते हैं। इस प्रकार के लोगों के बारे में बात होनी चाहिए, उनके जीवनयापन के लिए आज तक क्यों कुछ नहीं हुआ, 70 साल में भी लोग वहां पर ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनके बारे में पहले से क्यों नहीं सोचा गया? हम हवाई जहाज की यात्रा तो कर सकते हैं, ऊपर से हेलिकॉप्टर के माध्यम से भाषण देने के लिए जा सकते हैं, अपने लिए वोट मांगने के लिए जा सकते हैं, किन्तु बंधुओ, उनके बारे में ईमानदारी से सोचा जाए और उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं।

वहां पर पशु रखे जाते हैं और पशुओं के लिए वैटरनरी अस्पताल होने चाहिए, लेकिन वहां तो वैटरनरी डिस्पेंसरी तक नहीं है। अभी मैंने जिस गांव को गोद लिया है, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिस गांव को लिया है, उसमें अभी विकास का काम शुरू करवाया है। वह काम भी तीन वर्षों के बाद पूरा होगा, फिर वहां पर लोग आसानी से जा सकेंगे। इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहकर ये सारी चीज़ें हो रही

हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में केवल हम क्वेश्चनेयर ही नहीं बनाएं, पूछताछ न करें, बल्कि मैं कहता हूं कि आपने हम पर उम्मीदें लगायी हैं और हम आपकी उम्मीदों पर पूरे खरे उतरेंगे। आने वाले समय में हम इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे किसान का मामला होगा, चाहे पढ़े-लिखे नौजवानों का मामला होगा और हम बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वहां पर किसानों के लिए फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से 1400 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे कि वहां पर अच्छी तरह से फूड प्रोसेसिंग हो सके। इससे पहले इसके लिए 200 करोड़, 250 करोड़ रुपये देते थे और वह जाता कहां था ? आप जानते हैं कि अगर पिछले घोटालों को निकाला जाए, तो पूरे 12 लाख करोड़ रुपये का घोटाला था। वह पैसा कहां गया? अगर वह पैसा देश के विकास में लगता, उन कंदराओं में लगता, तो अपने देश का अच्छा विकास होता। आज यह देश सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। यह सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा जिस प्रकार की राह दिखाई गई है, उस राह को हमें देखना होगा, उस राह पर हमें चलना होगा। अगर हम ईमानदारी से इस राह पर चलेंगे, तो पूरा देश आगे बढ़ेगा।

दूसरा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत वहां पर इस प्रकार से योजनाएं बनायी गयी हैं कि बॉर्डर पर रहने वाले बंधुओं को सुविधाएं मिल सकें। पिछले दिनों में उनको केवल गोली मिलती थी, जिसके कारण वे वहां से उजड़कर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पीछे आते थे और उनको बसाने में 10-15 वर्ष लग जाते थे।

आज जैसे ही वे बंधु बॉर्डर एरिया से वहां पर आते हैं, उसी दिन से उनके लिए मकानों का किस प्रकार से निर्माण हो सके, किस प्रकार से उनको बसाया जाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। ये सारी योजनाएं कौन बना रहा है, किसके अंतर्गत बन रही हैं? अगर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत इस प्रकार की योजना न बने, तो वे बंधु उजड़कर रह जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, तो कश्मीर में 1990 से आज तक किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, किस प्रकार का वातावरण बना हुआ था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे साथ श्रीनगर में आइए, मैं पूरा कश्मीर घुमाकर लाता हूं, आपको बिल्कुल सुरक्षित और आराम से सारे टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाकर लाऊंगा।

(HMS/2J पर जारी)

BHS-HMS/2J/4.50

श्री शमशेर सिंह मन्हास (क्रमागत) : इस प्रकार का वातावरण किस ने खड़ा किया? यह हमारी सरकार ने किया है। हमारे गृह मंत्री ने किया है। महोदय, इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर इस प्रकार की बातों को लेकर हमें केवल questionnaire प्राप्त करना है, हमें पूछताछ करनी है, हमें नुक्ताचीनी करनी है, टीका-टिप्पणी करनी है, तो आप टीका-टिप्पणी करते रहिए, लेकिन हम वहां आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते रहेंगे क्योंकि लोगों की सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है, हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज़ है। यह देश मेरी मां है और मैं इस का पुत्र हूं और पुत्र होने के नाते मैं हमेशा मां की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, धन्यवाद। (समाप्त)

श्रीमती रेणुका चौधरी (आंध्र प्रदेश) : महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया है।

आप जानते हैं कि जब देश में बजट पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उस पर देश के मशहूर Economists बैठकर सोचते हैं, वे आंकड़े और दिशा जरूर बनाकर देते हैं, मगर भारतवासी और मेरे जैसी गृहस्थ महिला भी बजट की ओर देखती है कि हमारी जिंदगी पर इस का आने वाले साल में क्या असर पड़ने वाला है? हम कहां पैसे की बचत करें? वह कैसे परिवार की प्रोग्रेस देखे, बच्चों को कैसे शिक्षित बनाए और अगर एक सामान्य किसान का परिवार है, तो उसे कई बातों को सोचना पड़ता है। इसलिए जब बजट पेश होता है, तो सिर्फ बातों से हवा महल की तरह बात करेंगे, तो कुछ नहीं मिलता है।

महोदय, ये मेरे colleagues यहां इतनी देर से खड़े हैं, ये इतने दिनों से आवाज उठा रहे हैं और हमारे respected colleague Dr. K. Keshava Rao जी बहुत गर्म होकर बोले हैं। वास्तव में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हमारे जुड़वां बच्चे थे, लेकिन आज एक तेलुगू दूसरे तेलुगू से लड़ रहा है, खून बह रहा है, वहां नदी-तालाब सूख गए हैं। एक नया राज्य बनना था, मगर हुआ क्या? अगर कोई फैसला इस घर में होता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसे निभाया जाएगा? अगर सरकार बदल जाती है तो क्या वायदा निभाया नहीं जाता है? Why has Andhra Pradesh not been given their status as a special category status? Why have they not been given? इन को मना करने क्या कारण है आपके पास? You had said that you will

allocate funds. What is the percentage that you have actually allocated? Do you know what is happening in Telangana as well? Under PMGSY, you have given us tokenism. हम tribal welfare development के लिए जरूर budget heads के नीचे गए हैं। मेरा जिला खम्मम है, जहां तेलंगाना में सब से ज्यादा tribals रहते हैं। हमारे तंडागुडम में, हमने जो उसे नाम दिया है, वहां हमें चलने का अधिकार नहीं है। वहां हमारे घरों से सड़क तक पहुंचने में तीन-तीन दिन लगते हैं। महोदय, यह बहुत बेरहम सरकार है और ये सिर्फ दिखाने के लिए बजट में बड़ी-बड़ी बातें बोलती है। वास्तव में हो क्या रहा है? आपने किसानों को बहुत उम्मीद दिलायी कि आप किसान का बजट पेश कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि शायद ऐसा होगा। मैं आपकी मजबूरी समझती हूं। आज आप को देश भर के किसानों की आह लग रही है। यह बात आपको समझ आ गयी है और अगले साल चुनाव होंगे, इसलिए आप जल्दबाजी में किसान का बजट लेकर आए। इस में आपने उन्हें कितने पैसे दिए हैं? What is your overall percentage that you have increased in the allocation? यह मुझे समझाइए। आप एम0एस0पी0 देंगे। आप समझते हैं कि एम0एस0पी0 क्या चीज है? आप और आप के बाबू लोग ए0सी0 कमरों में बैठकर, जिन्होंने कभी जमीन को जोता नहीं, जब आपने कभी देखा ही नहीं, वह तकलीफ आपको महसूस ही नहीं हुई ...

(2 के/एएससी पर जारी)

ASC-RL/4.55/2K

श्रीमती रेणुका चौधरी (क्रमागत) : जब हम खेत में खड़े रहते हैं और हमारी फसल सूख जाती है या bumper crop लेकर हम मार्केट चले जाते हैं और अच्छा rate रेट नहीं मिलता है, तो क्या आप जानते हैं कि वह तकलीफ कैसी है? क्या आप जानते हैं कि जो हम महिला किसान होती हैं, तो हमने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है, ताकि हमारी फसल अच्छी पैदा हो? ...(व्यवधान)....हमें समझ में आ गया कि आपको जानकारी नहीं है। आपके सवालों से समझ में आ जाता है कि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप और ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं कहती हूं कि आप सोच-समझकर कदम उठाएं। किसान का आक्रोश खत्म होने वाला नहीं है, यह तो शुरुआत है, मेरे भाई! हम इलेक्शन तक देखते रहेंगे कि MSP क्या है और किसान का ABC क्या है, आपको समझ में आएगा। आप कह रहे हैं कि हम इसको extension of MSP देते जा रहे हैं बाकी crops के लिए, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला नीति आयोग करेगा मगर यह नहीं कहा गया कि इसका खर्चा और कर्ज़ा कहां से आएगा। इसके लिए कोई Budget allocation ही नहीं है और Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के लिए कोई allocation नहीं है, तो फिर आप Revised Estimate में क्या लेकर आए हैं? मुझे यह बात समझ में आ रही है, लेकिन इन नए राज करने वालों की समझ में नहीं आ रही है। आपके यहां तो कह देते हैं कि लाल किले से भी लोग बोलते हैं, मगर होता क्या है कि घूम-फिर कर आप राज्य सरकारों के ऊपर खर्चा डाल देते हैं और हमारी राज्य सरकारें यह खर्चा उठा नहीं सकती हैं। मगर

आप ड्रामा तो बहुत अच्छा करते हैं। आप देखते रहिए, आज के दिन जब किसान मार्केट चला जाता है, तो क्या आप उसको .....(व्यवधान)... आप मेरी बात विनम्रता से सुनिए। आपको सच सुनने का हौसला भी रखना चाहिए, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। मैं जानती हूं कि कभी-कभी यह सच चुभ जाता है। ...(व्यवधान).... आपने हाउस में आकर कह दिया, We are forced to bring up the price of farmers. महोदय, आज कम से कम यह सरकार किसानों के बारे में बोल रही है और ये कम से कम उनका नाम तो ले रहे हैं। पहले तो यह भी नहीं होता था। But, what are the outlays for the market intervention and price support scheme? जो बहुत जरूरी है। ये क्या करें, उसमें गिरावट है। From Rs. 950 crores of Revised Estimate of last year to 200 करोड़। आप हमें 200 करोड़ में किसान का भविष्य दिखा रहे हैं, वाह रे वाह ! यह मुझे समझ में नहीं आया। आपने जो यह NPA write-off industry के लिए दिया है, इससे किसी की एक दमड़ी की भी नौकरी नहीं लगी। जब आपने industry में relief दिया है, तो हमारे किसानों को कर्जे में relief नहीं देंगे? किसान की debt relief के लिए आपने आज तक दो कौड़ी भी नहीं दी है। हमारे किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आज मुझे यह कहते हुए ज्यादा दुख हो रहा है कि मेरे क्षेत्र खम्मम में भी एक किसान ने आत्महत्या की है। उसने दो बोर वैल खोदे, लेकिन उनमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकाला। हम वहां कपास bumper crop उगाते हैं, पैडी उगाते हैं और मिर्च उगाते हैं। एक बार कर्जे के रूट पर चले गए, तो किसान को कोई यू टर्न नहीं मिलता है। इन tenant farmers की क्या हालत है? आप लोगों ने कभी जमीन कोल पर ली है, क्योंकि

हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि अपनी जमीन रहे। जब हम कोल पर जमीन लेते हैं और फसल बोते समय नुकसान हो जाता है, मैंने अपने बजट में बड़े गौर से देखा है, इनके लिए एक भी लफ्ज़ नहीं है, एक सोच नहीं है और एक विचार नहीं है कि कोलदार का क्या हाल होगा? ....(समय की घंटी).... महोदय, माफ कीजिए। आप मेरी तरफ देखकर घंटी मत बजाइए। आप देखिए कि सूइसाइड करने वालों में तेलंगाना और ओडिशा में जितने भी कोलदार tenant farmers हैं, इनके लिए तो कोई सहूलियत नहीं है और इनके लिए इस बजट में कोई सपोर्ट भी नहीं है।

(2L/LPपर जारी)